**भारत सरकार**

**शहरी विकास मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं0 150**

**5 दिसम्‍बर, 2013 को उत्तर के लिए**

**2021 ls 2051 ds nkSjku 'kgjh tula[;k**

**150- Mkñ vkjñ y{e.ku%**

**D;k 'kgjh fodkl ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%**

**¼d½ D;k ljdkj us 'kgjh vkcknh] tks 2021 esa c<+dj 473 fefy;u rFkk 2051 esa c<+dj 820 fefy;u gks tk,xh] dh vkokxeu laca/kh vko';drkvksa dks iwjk djus ds fy, dksbZ uhfr rS;kj dh gS( ;fn gka] rks rRlaca/kh C;kSjk D;k gS(**

**¼[k½ D;k ljdkj dks bl rF; dh tkudkjh gS fd Hkkoh vko';drkvksa ds fy, nwj n`f"V ds vHkko ds dkj.k 'kgjh {ks=ksa esa i;kZIr rFkk csgrj volajpuk ds l`tu dh fLFkfr vkSj [kjkc gks tkrh gS( vkSj**

**¼x½ ;fn gka] rks bl laca/k esa mBk, x, lq/kkjkRed dne D;k gSa\**

**उत्तर**

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्रीम‍ती दीपा दासमुंशी)**

1. : जी हां। शहरी जनसंख्‍या की परिवहन जरूरतों को पूरा करने के लिए केन्‍द्रीय सरकार ने राष्‍ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी), 2006 बनायी है।
2. जी, हां। एनयूटीपी, 2006 का निर्माण हमारे शहरों को अत्‍यंत वास-योग्‍य बनाने और उन्‍हें इस प्रकार समर्थ बनाने की दृष्टि से किया गया है ताकि वे अग्रणी शहर का रूप ले सकें, जिससे 21वीं शताब्‍दी में भारत के विकास को शक्ति मिलेगी। सभी शहरी परिवहन परियोजनाओं का आरंभ इसी दृष्टि के अनुरूप और विभिन्‍न राज्‍यों/नगरों/कस्‍बों में परिवहन की भावी अपेक्षाओं का यथोचित ध्‍यान रखते हुए किया गया है।
3. भारत सरकार ने आवागमन संबंधी भावी आवश्‍यकताओं को ध्‍यान में रखते हुए विभिन्‍न उपाए किए हैं। ये उपाय इस प्रकार हैं:व्‍यापक आवागमन योजनाएं (सीएमपी) तैयार करने और अन्‍य यातायात एवं परिवहन अध्‍ययन/सर्वेक्षणों के लिए वित्‍त व्‍यवस्‍था, एमआरटीएस के लिए विस्‍तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए वित्‍त व्‍यवस्‍था, जवाहरलाल नेहरू राष्‍ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत द्रुत बस परिवहन प्रणाली (बीआरटीएस) और बसों के लिए वित्‍त व्‍यवस्‍था, विभिन्‍न शहरों में मैट्रो रेल परियोजनाओं को स्‍वीकृत करना और वित्‍त व्‍यवस्‍था करना, टूलकिट तैयार करके क्षमता का निर्माण करना तथा कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के आयोजन के माध्‍यम से प्रशिक्षण सामग्री और मार्गदर्शन से संबंधित अन्‍य दस्‍तावेज।

सरकार ने 21 बीआरटीएस परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया है, जिसमें से 3 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और शेष परियोजनाएं कार्यान्‍वयन के विभिन्‍न चरणों में हैं। जेएनएनयूआरएम के अन्‍तर्गत दिल्‍ली और अन्‍य मैट्रो शहरों सहित सभी 61 मिशन मोड शहरों के लिए कुल 15260 आधुनिक सुव्‍यवस्थित परिवहन समर्थित बसों की मंजूरी पहले ही प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा, पर्वतीय राज्‍यों पर विशेष ध्‍यान केन्द्रित करते हुए, सभी शहरों/नगरों/शहरी समूहों के लिए 2013-14 के दौरान केन्‍द्र सरकार द्वारा 10,000 आधुनिक सुव्‍यवस्थित परिवहन समर्थित बसों की मंजूरी के लिए एक नई योजना का अनुमोदन किया गया है। डिपुओं, सुव्‍यवस्थित परिवहन प्रणाली आदि जैसी आनुषंगिक आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अतिरिक्‍त केन्‍द्रीय सहायता भी उपलब्‍ध करायी जाएगी। सरकार ने तेजी से बढ़ती आबादी के लिए परिवहन के साधनों की सुलभता के लिए सुरक्षित, किफायती, द्रुत, सुविधापूर्ण, विश्‍वसनीय और सततता प्रदान करने के लिए दिल्‍ली और राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), कोलकाता, बंगलौर, जयपुर, कोची, चेन्‍नई, हैदराबाद और मुंबई में मैट्रो रेल परियोजनाओं को भी स्‍वीकृति प्रदान की है।

\*\*\*\*\*